जगदेव सिंह बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी

19 नवंबर, 1990

समतुल्य उद्धरण: एआईआर 1991 पीएच 149, (1991) 99 पीएलआर 237

बेंच: जे गुप्ता, एस सोढ़ी, आर मोंगिया

न्यायमूर्ति आरएस मोंगिया,

1. इस याचिका को स्वीकार करते समय, मोशन बेंच ने इच्छा जताई कि इस मामले का निर्णय एक बड़ी बेंच का गठन करके किया जाए, जैसा कि इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने हाजी अनवर अहमद खान बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड , एआईआर 1980 पुन एंड हर में व्यक्त किया था। 306, पुनर्विचार आवश्यक। बाद में, एक अन्य याचिका - सीडब्ल्यूपी नंबर 2443, 1989 - राजविंदर सिंह बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, को भी स्वीकार कर लिया गया और इस रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी नंबर 6009, 1987) के साथ सुनवाई करने का आदेश दिया गया। इस मामले में भी निर्धारण के लिए यही कानून बिंदु सामने आया। पहला मामला, यानी 1987 का सीडब्ल्यूपी नंबर 6009, हरयाणा सहकारी समिति अधिनियम के तहत है; जबकि बाद वाला मामला, यानी 1989 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2443, पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत है ।

2. कानून का प्रश्न जिसके निर्धारण की आवश्यकता है वह यह है कि क्या पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1961, नियमों और उसके तहत बनाए गए उपनियमों (साथ ही हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 के तहत) में किसी प्रावधान के अभाव में , किसी सहकारी समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/ किसी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नियम और उसके तहत बनाए गए उपनियम) क्या ऐसा प्रस्ताव लाने की अनुमति है? इस धारणा पर एक प्रस्ताव कि ऐसी कोई निहित शक्ति है।

3. शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि इसी तरह का एक मामला हाजी अनवर अहमद खान के मामले (एआईआर 1980 पुन और हर 306) (सुप्रा) में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के समक्ष विचार के लिए आया था, जो पंजाब वक्फ अधिनियम के तहत एक मामला था। , 1954, जिसमें यह माना गया कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, हालांकि वक्फ अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत हटाने के लिए कोई विशेष शक्ति नहीं थी। वक्फ बोर्ड के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर एक अध्यक्ष जैसा कि शुरुआती पैराग्राफ में कहा गया है, बाद की डिवीजन बेंच ने हाजी अनवर अहमद खान के मामले (एआईआर 1980 पुन एंड हर 306) (सुप्रा) में निर्धारित कानून की शुद्धता पर संदेह किया और मामले की शुद्धता पर पुनर्विचार के लिए मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया। उक्त मामला.

4. इन दोनों मामलों के तथ्यों को विस्तार से बताना जरूरी नहीं है. यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6009 में, याचिकाकर्ता जगदेव सिंह को प्रावधानों के तहत 8 अप्रैल, 1985 को रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (इसके बाद बैंक कहा जाएगा) के निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में चुना गया था। हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 (इसके बाद इसे हरियाणा अधिनियम कहा जाएगा) और उसके तहत बनाए गए नियम। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 6 जून, 1985 को निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया।

हरियाणा अधिनियम की धारा 28(4) के तहत, एक सहकारी बैंक के निदेशक मंडल/एक सहकारी समिति की प्रबंध समिति- ऑपरेटिव सोसाइटी, चुनाव की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पद पर रहती है, जब तक कि सहकारी सोसाइटी के अधिनियम, नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रार द्वारा उसे हटा नहीं दिया जाता। बैंक के प्रबंध निदेशक ने 16 सितंबर, 1987 को निर्धारित निदेशक मंडल की बैठक के लिए एक एजेंडा जारी किया, आइटम नंबर 1 में बैंक के छह निदेशकों द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करना और निर्णय लेना था। निदेशक मंडल यानि याचिकाकर्ता। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस दलील पर वर्तमान याचिका दायर की थी कि हरियाणा अधिनियम, नियमों या उपनियमों के तहत अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों के खिलाफ 'अविश्वास' प्रस्ताव लाने या पारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। बैंक के निदेशक मंडल.

5. दूसरे मामले (सीडब्ल्यूपी नंबर 2443/1989) में भी ऐसे ही तथ्य हैं, जो पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत है । पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे पंजाब अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 26 के तहत , एक सहकारी समिति की प्रबंध समिति/सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के कार्यालय का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तीन साल के रूप में. इस मामले में निदेशक मंडल का चुनाव 30 दिसंबर, 1987 को हुआ और 27 जनवरी, 1988 को याचिकाकर्ता राजविंदर सिंह को उक्त निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया। 15 फरवरी, 1989 को, बैंक के सात निदेशकों ने कार्यवाही दर्ज की जिसमें दिखाया गया कि याचिकाकर्ता को अविश्वास मत द्वारा राष्ट्रपति के कार्यालय से हटा दिया गया था और उसके स्थान पर एक अन्य निदेशक को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यह वह कार्रवाई थी जिसे उक्त रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, 1987 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6009 के साथ सुनवाई करने का आदेश दिया गया था।

6. यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पंजाब अधिनियम या हरियाणा अधिनियम या इन संबंधित अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों और उपनियमों के तहत, किसी भी मामले के लिए किसी अध्यक्ष/अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। अविश्वास मत से पदाधिकारी। पंजाब अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम वास्तव में किसी सहकारी समिति/बैंक के अध्यक्ष/अध्यक्ष या उस मामले में किसी पदाधिकारी के चुनाव की बात नहीं करते हैं। यह केवल सहकारी समिति के उपनियम हैं जो पदाधिकारियों के चुनाव और उनके कार्यकाल का प्रावधान करते हैं। हरियाणा अधिनियम की धारा 30 पदाधिकारियों के चुनाव की बात करती है, लेकिन पदाधिकारियों के कार्यकाल का प्रावधान नहीं करती है। हरियाणा अधिनियम की घोषणा से पहले, हरियाणा में सहकारी समितियाँ पंजाब अधिनियम द्वारा शासित होती थीं , जैसा कि हरियाणा में लागू था। 1976 के अधिनियम संख्या 36 द्वारा, हरियाणा राज्य ने पंजाब अधिनियम में धारा 26(7) जोड़ दी थी, जिससे समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। और समिति का कार्यकाल हरियाणा पर लागू पंजाब अधिनियम की धारा 26(6) के तहत तीन वर्ष निर्धारित किया गया था। हालाँकि, हरियाणा अधिनियम विशेष रूप से पदाधिकारियों का कार्यकाल तय नहीं करता है, और इसलिए, इसे सोसायटी की प्रबंध समिति के कार्यकाल के साथ जुड़ा हुआ माना जा सकता है, जिसे धारा 28 के तहत तीन साल के लिए तय किया गया है। 4)हरियाणा एक्ट के.

7. जहां तक पंजाब मामले का सवाल है, बैंक के सीडब्ल्यूपी नंबर 2443 ऑफ 1989), उपनियम 30 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और उनके कार्यकाल की परिकल्पना की गई है। उपनियम 30 नीचे उद्धृत किया गया है:--

"30, निदेशक मंडल अपने में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और/या एक प्रबंध निदेशक का चुनाव करेगा। वे तीन साल के लिए पद पर रहेंगे।"

8. पंजाब अधिनियम और हरियाणा अधिनियम दोनों की योजना यह है कि सहकारी समिति का सामान्य निकाय एक प्रबंध समिति (सहकारी बैंक के मामले में निदेशक मंडल के रूप में जाना जाता है) का चुनाव करता है, जिसका कार्यकाल जैसा कि ऊपर कहा गया है, तीन वर्ष निर्धारित हैं। प्रबंध समिति/निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या अलग-अलग सोसायटी में अलग-अलग होती है। (पंजाब अधिनियम की धारा 26 देखें - हरियाणा अधिनियम की धारा 28 के बराबर)। 'समिति' को पंजाब अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत परिभाषित किया गया है और 'सोसाइटी के अधिकारी को पंजाब अधिनियम की धारा 2(एच) के तहत परिभाषित किया गया है। प्रबंध समिति के सदस्य या बोर्ड के निदेशक जैसा भी मामला हो, निदेशक अपने में से एक अध्यक्ष/अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जिसका कार्यकाल भी ऊपर बताए अनुसार निर्धारित होता है। पंजाब अधिनियम की धारा 27 (हरियाणा अधिनियम की धारा 34 और 35 के बराबर), उसमें उल्लिखित कुछ आधारों पर समिति या उसके सदस्यों को हटाने या निलंबित करने का प्रावधान है। पंजाब नियमों के आर. 26 (हरियाणा नियम, 1989 के आर. 28 के बराबर) के तहत, यह प्रदान किया गया है कि जब कोई सदस्य समिति इस प्रकार अपना पद धारण करना बंद कर देती है। पंजाब नियमों का आर. 25 किसी समिति की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ निर्धारित करता है। (हरियाणा नियम, 1989 के आर. 27 के समतुल्य)।

9. धारा 2 (बी), 2 (एच), 26 और 27 और आरआर। पंजाब अधिनियम और नियमों के 25 और 26 , त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किए गए हैं:--

"2(बी) 'समिति' का अर्थ है किसी सहकारी समिति का शासी निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे समिति के मामलों का प्रबंधन सौंपा जाता है;

2(ज) 'अधिकारी' का अर्थ है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सचिव, प्रबंधक, समिति के सदस्य, कोषाध्यक्ष, परिसमापक, प्रशासक और इसमें नियमों या ब्यू- के तहत सशक्त कोई भी व्यक्ति शामिल है। सहकारी समिति के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने के लिए कानून।

26. समिति के सदस्यों का चुनाव एवं नामांकन.-- किसी सहकारी समिति की समिति के सदस्यों का चुनाव निर्धारित तरीके से किया जायेगा और कोई भी व्यक्ति तब तक निर्वाचित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह समिति का शेयरधारक न हो.

(1ए) किसी भी सहकारी समिति की समिति रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन समिति के सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से समिति के संचालन क्षेत्र को क्षेत्रों में विभाजित कर सकती है।

(1 बी) एक समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा;

बशर्ते कि एक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति या अधिसूचित वस्तु का कारोबार करने वाली समिति अपने उपनियमों में यह प्रावधान कर सकती है कि उसकी समिति के यथासंभव एक तिहाई सदस्य उसके उपनियमों और में निर्धारित तरीके से हर साल सेवानिवृत्त होंगे। ऐसा प्रावधान लागू होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप हुई रिक्तियों को निर्धारित तरीके से भरा जाएगा।

स्पष्टीकरण.-- दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति या सोसायटी सौदे के मामले में-

पंजाब सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारंभ से पहले पंजीकृत अधिसूचित वस्तु में, समिति की उपरोक्त संख्या की पहली सेवानिवृत्ति उस तारीख की एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर तुरंत होगी, जिस दिन संशोधन किया गया था। ऐसी सेवानिवृत्ति के लिए प्रदान करने वाले समाज के उपनियम लागू होते हैं।

(1सी) प्रत्येक समिति अपने कार्यकाल की समाप्ति से नब्बे दिन पहले, इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए उपनियमों के अनुसार एक नई समिति के गठन की व्यवस्था करेगी।

(आईडी) जहां किसी समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है और इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और उप-कानूनों के अनुसार कोई समिति गठित नहीं की गई है, रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, एक सरकारी कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है। प्रशासक ऐसी अवधि के लिए, जो समय-समय पर, आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है और प्रशासक, अपनी नियुक्ति की अवधि की समाप्ति से पहले, इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक नई समिति के गठन की व्यवस्था करेगा। और उसके तहत बनाए गए उपनियम:

बशर्ते कि कुल अवधि जिसके लिए प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है, किसी भी मामले में एक वर्ष और छह महीने से अधिक नहीं होगी और यदि ऐसी अवधि को एक वर्ष से अधिक बढ़ाया जाना है, तो रजिस्ट्रार, निर्दिष्ट सहकारी समिति के मामले को छोड़कर, दूसरे परंतुक में, इस तरह के विस्तार के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करें;

बशर्ते कि किसी सहकारी समिति के मामले में कुल अवधि जिसके लिए प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है, चार साल तक बढ़ सकती है, जहां सरकार ने बीस लाख रुपये या उससे अधिक की शेयर पूंजी की सदस्यता ली है या गारंटी दी है प्रशासक की नियुक्ति की तारीख से ठीक पहले पांच साल की अवधि के दौरान किसी भी समय उस सोसायटी द्वारा ऋण के माध्यम से जुटाई गई दस लाख रुपये या उससे अधिक की राशि का पुनर्भुगतान और संचित हानि। पांच लाख रुपये से अधिक, और जहां ऐसी सोसायटी के मामले में पंजाब सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारंभ होने से ठीक पहले इस परंतुक द्वारा निर्धारित तीन वर्षों की कुल अवधि, ऐसे प्रारंभ से पहले समाप्त हो जाने पर प्रशासक की नियुक्ति की अवधि में विस्तार उसकी समाप्ति तिथि से पूर्वव्यापी रूप से किया जा सकता है, हालाँकि, कुल अवधि जिसके लिए वह पद धारण कर सकता है, चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1ई) उप-धारा के प्रावधान। (3) और उप-सेक. धारा 27 का (4) उप-धारा के तहत नियुक्त प्रशासक पर लागू होगा। (आईडी) मानो उस धारा के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया हो।

(आईएफ) इस धारा में किसी भी बात के बावजूद, जहां किसी सोसायटी के उपनियम ऐसा प्रावधान करते हैं, पहली समिति उन उपनियमों में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा नामित की जा सकती है।

(2) उपधारा में किसी बात के होते हुए भी। (1).-

(ए) जहां सरकार ने किसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी की सदस्यता ली है या किसी सहकारी समिति, सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उठाए गए ऋणों के लिए जारी किए गए डिबेंचर पर मूलधन की पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की गारंटी दी है इस निमित्त उसे समिति में उतनी संख्या में व्यक्तियों को नामांकित करने का अधिकार होगा, जो उसके कुल सदस्यों की संख्या के तीन या एक तिहाई से अधिक न हो, जो भी कम हो, जैसा कि सरकार निर्धारित कर सकती है:

बशर्ते कि जहां सरकार ने किसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी में बीस लाख रुपये या उससे अधिक की सीमा तक सदस्यता ली हो, सरकार, समिति के उपनियमों में किसी भी बात के बावजूद, ऐसा कर सकती है।

(ए) उपरोक्त तरीके से नामित सदस्यों में से एक को ऐसी सोसायटी की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करें; या

(बी) उपरोक्त तरीके से नामित लोगों के अलावा एक अन्य सदस्य को नामांकित करें और उसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करें: बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा, पंजाब सिविल सेवा का सदस्य न हो (कार्यकारी शाखा) या एक उप रजिस्ट्रार, एक संयुक्त रजिस्ट्रार या एक अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ।

(बी) जहां औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम या सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी अन्य वित्तपोषण संस्थान ने किसी सहकारी समिति, औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम या अन्य वित्तपोषण संस्थान को वित्त प्रदान किया है। हो सकता है, समिति में एक व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार होगा।

(2ए) जहां सरकार सीएल के प्रावधान के तहत एक अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करती है। (ए) उप-सेकंड का। (2), अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले पद धारण कर रहा हो, ऐसी नियुक्ति पर पद धारण करना बंद कर देगा।

(2बी) जैसा भी मामला हो, सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के प्रबंध निदेशक की सेवा के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष को देय पारिश्रमिक, जैसा भी मामला हो होगा, का भुगतान सहकारी समिति की निधि से किया जाएगा।

(3) उप-धारा के तहत नामांकित व्यक्ति। (2) जैसा भी मामला हो, सरकार या निगम या अन्य वित्तीय संस्थान की मर्जी तक पद पर रहेगा।

(4) जहां, एक सहकारी समिति में, जिसमें सरकार द्वारा समिति की कार्यशील पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक उधार लेने की गारंटी के माध्यम से देयता के लिए शेयरों की सदस्यता ली गई है, किसी के संबंध में मतभेद है यदि मामला समिति के नामित सदस्यों और उसके अन्य सदस्यों के बीच उठता है, तो मामले को समिति द्वारा सरकार को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा और यह इस तरह से कार्य करेगा जैसे कि यह समिति द्वारा लिया गया निर्णय हो।

धारा 27 . समिति या उसके सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना.-- (1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, कोई समिति या किसी समिति का कोई सदस्य लगातार उसके द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों के पालन में चूक करता है या लापरवाही बरतता है अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम या उपनियम, या कोई ऐसा कार्य करता है जो सोसायटी या उसके सदस्यों के हितों के लिए प्रतिकूल है, सहकारी समिति द्वारा किए गए उत्पादन या विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में चूक करता है, रजिस्ट्रार कर सकता है जैसा भी मामला हो, समिति या सदस्य को लिखित आदेश द्वारा अपनी आपत्तियां, यदि कोई हो, बताने का उचित अवसर देने के बाद-

(ए) समिति को हटा देगा, और एक सरकारी कर्मचारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगा, जो आदेश में निर्दिष्ट एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी के मामलों का प्रबंधन करेगा;

(बी) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और उप-कानूनों के अनुसार, सदस्य को हटा दें और निवर्तमान सदस्य की शेष अवधि के लिए रिक्ति को भरें।

(2) जहां रजिस्ट्रार, उप-धारा के तहत कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहा है। (1) की राय है कि कार्यवाही की अवधि के दौरान समिति या सदस्य का निलंबन सहकारी समिति के हित में आवश्यक है, तो वह समिति या सदस्य को, जैसी भी स्थिति हो, निलंबित कर सकता है, और जहां समिति निलंबित है , कार्यवाही पूरी होने तक समाज के मामलों के प्रबंधन के लिए ऐसी व्यवस्था करें जो वह उचित समझे।

परन्तु यह कि यदि समिति या सदस्य को इस प्रकार निलम्बित किया गया है तो उसे हटाया नहीं जायेगा अथवा उसे बहाल कर दिया जायेगा तथा निलम्बन की अवधि उसके कार्यकाल में गिनी जायेगी।

(3) इस प्रकार नियुक्त प्रशासक, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अधीन और ऐसे निर्देशों के अधीन होगा जो वह समय-समय पर दे सकता है, समिति के या समाज के किसी भी अधिकारी के सभी या किसी भी कार्य को करने की शक्तियां होंगी और समाज के हित में आवश्यक सभी कार्रवाई करें।

(4) रजिस्ट्रार प्रशासक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को देय पारिश्रमिक तय कर सकता है और ऐसे पारिश्रमिक की राशि और सोसायटी के प्रबंधन में होने वाली अन्य लागत, यदि कोई हो, उसके फंड से देय होगी।

(5) प्रशासक, अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले, इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और उपनियमों के अनुसार एक नई समिति के गठन की व्यवस्था करेगा।

(6) उप-धारा के तहत कोई भी कार्रवाई करने से पहले। (1) सहकारी समिति के संबंध में, रजिस्ट्रार उस वित्तपोषण बैंक से परामर्श करेगा जिसकी समिति ऋणी है।

(7) एक सदस्य जिसे उप-धारा के तहत हटा दिया जाता है। (1) रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी समिति में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

नियम 25. समिति की सदस्यता के लिए अयोग्यता.-- कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि:-

(ए) वह किसी भी सहकारी समिति के प्रति देय किसी भी राशि के संबंध में चूककर्ता है या किसी सहकारी समिति को उसकी अधिकतम क्रेडिट सीमा से अधिक राशि बकाया है;

(बी) उसका किसी भी अनुबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित है, जिसमें सहकारी समिति एक पार्टी है, सहकारी समिति के साथ एक सदस्य के रूप में किए गए लेनदेन को छोड़कर, जैसा कि उप-नियम में कहा गया है, समिति के उद्देश्य के अनुसार कानून;

(सी) वह नामांकन पत्रों की जांच की तारीख से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय, किसी भी निजी व्यवसाय व्यापार या किसी भी प्रकार के पेशे में लगा हुआ है जो समाज द्वारा किया जाता है;

(डी) उसने नामांकन पत्रों की जांच की तारीख से पहले पांच साल की अवधि के दौरान बेईमानी या नैतिक अधमता से जुड़ा कोई अपराध किया है;

(ई) वह आर 26 में निहित किसी भी प्रतिबंध के अधीन है;

(एफ) नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से पहले 12 महीने की अवधि के दौरान, वह सदस्य के रूप में निष्क्रिय रहा है या सहकारी समिति, जिसका वह सदस्य है, के अलावा अन्य एजेंसियों के माध्यम से वही व्यवसाय कर रहा है सहकारी समिति द्वारा किया जा रहा है;

(छ) वह किसी भी सहकारी समिति का सदस्य है जिसने कार्य करना बंद कर दिया है या जिसने अपने उपनियमों में बताए गए उद्देश्यों को पूरा नहीं किया है और रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए 'डी' श्रेणी की समितियों की सूची में शामिल किया गया है या है किसी सोसायटी की निर्वाचित समिति का सदस्य जो समापन प्रक्रिया के अधीन है।

(जीजी) वह रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई 'डी' क्लास सोसायटी की सूची में या आदेश के संचालन में ऐसी सोसायटी को शामिल करने की तारीख से पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी सहकारी सोसायटी का सदस्य नहीं रह गया है। अधिनियम की धारा 57 के तहत ऐसी सोसायटी को बंद करना ।

बशर्ते कि सीआई में कुछ भी न हो। (जी) और (जीजी) को किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित माना जाएगा यदि समापन प्रक्रिया के तहत सोसायटी, जिसका वह सदस्य है, सीमित या असीमित दायित्व वाली सोसायटी है और वह व्यक्ति ज़मानत के रूप में दायित्व सहित अपनी सभी देनदारियों का निर्वहन करता है मूल्यांकन आदेशों की प्राप्ति से दो महीने के भीतर ऐसी सोसायटी के संबंध में यदि कोई हो;

(ज) उसने समाज के उपनियमों में निर्धारित किसी अन्य अयोग्यता को जन्म दिया है।

नियम 26. समिति की सदस्यता की समाप्ति.-- समिति का कोई सदस्य अपना पद धारण करना बंद कर देगा यदि वह:-
-

(ए) उपनियमों में निर्धारित अवधि के लिए सहकारी समिति को देय किसी भी राशि के संबंध में चूक करना जारी रखता है;

(बी) सदस्य बनना बंद कर देता है;

(सी) दिवालिया घोषित कर दिया गया है;

(डी) विकृत दिमाग का हो जाता है;

(ई) बेईमानी या नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है; या

(एफ) किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है जो उसे चुनाव लड़ने से रोकता, अगर उसने चुनाव से पहले अयोग्यता का सामना किया होता।

10. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री बीएस खोजी ने तर्क दिया कि कानून या उपनियमों के तहत तय किए गए अध्यक्ष/अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के कार्यकाल की अवधि को कम नहीं किया जा सकता है। अधिनियम, नियमों या उपनियमों में किसी विशिष्ट शक्ति के अभाव में किसी भी समय बैंक के प्रबंध समिति के सदस्यों/निदेशकों की खुशी, इच्छा या इच्छा पर। उन्होंने तर्क दिया कि पदाधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जाता है बल्कि निर्वाचित किया जाता है और उन्हें हटाने या अल्पावधि में कटौती करने की विधि और तरीका अधिनियम, नियमों या उपनियमों के तहत प्रदान किया जाना चाहिए। अविश्वास मत द्वारा पदाधिकारियों को हटाना क़ानून, नियमों या उपनियमों में प्रदान नहीं किया गया है, उस शक्ति को क़ानून, नियमों या उपनियमों में नहीं पढ़ा जा सकता है और इसे अंतर्निहित नहीं माना जा सकता है या उस प्राधिकारी में निहित निहित शक्ति जिसने पदाधिकारियों को चुना था। विद्वान वकील के अनुसार, जनरल क्लॉजेज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जहां किसी प्राधिकारी को नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की जाती है, उसी प्राधिकारी के पास इस प्रकार नियुक्त किसी भी व्यक्ति को निलंबित या बर्खास्त करने की भी शक्ति होगी।

11. विद्वान वकील ने यह कहकर अपने तर्क का समर्थन किया कि पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम और पंजाब नगरपालिका अधिनियम जैसे स्थानीय निकायों से संबंधित समसामयिक विधानों में इसी विधानमंडल ने अध्यक्ष या पदाधिकारियों को हटाने का प्रावधान किया था। अविश्वास मत से. यदि, उनके अनुसार, उसी विधानमंडल ने सहकारी अधिनियम , नियमों या उपनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया है, तो इसे नहीं पढ़ा जा सकता है और बल्कि यह माना जाना चाहिए कि विधानमंडल कभी भी ऐसी शक्ति नहीं चाहता था समिति के सदस्यों/बैंक के निदेशकों को प्रदान किया जाएगा।

12. उपर्युक्त दलीलों के लिए, विद्वान वकील ने वीरमाचानेनी वेंकट नारायण बनाम सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार, एलुरा, पश्चिम गोदावरी जिला आईएलआर (1975) अंध प्रा 242 मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया। हिंदूराव बलवंत पाटिल बनाम कृष्णराव परशुराम पाटिल एआईआर 1982 बॉम्बे 216 में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला , साथ ही जोगिंदर सिंह, प्रेसिडेंट रूपार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रूपर बनाम रजिस्ट्रार मामले में इस कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला ; सहकारी समितियां, पंजाब, (977 पुं एलजे 310। विद्वान वकील ने कहा कि हाजी अनवर अहमद खान के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का फैसला (एआईआर 1980 पुं और हर 306) (सुप्रा) सही कानून नहीं बनाता है क्योंकि डिवीजन बेंच ने वीरमाचानेनी वेंकट नारा-याने के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अलग

दृष्टिकोण लेने के लिए सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 372 (1) पर गलत तरीके से भरोसा किया था। केस (आईएलआर (1975) अंध प्रा 242) (सुप्रा)।

13. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जिस निकाय के पास चुनाव करने की शक्ति है, उसके पास हमेशा निर्वाचित व्यक्ति को हटाने की अंतर्निहित शक्ति होती है और इसलिए, यदि प्रबंध समिति के सदस्यों का बहुमत होता है सहकारी समिति ने एक पदाधिकारी पर से विश्वास खो दिया था, प्रबंध समिति के सदस्यों/बैंक के निदेशकों के पास हमेशा ऐसे पदाधिकारी को हटाने की अंतर्निहित शक्ति थी और इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें आनंद नहीं मिला, उन्हें जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। प्रबंध समिति के अधिकांश सदस्यों का विश्वास, जो बदले में सामान्य निकाय के प्रतिनिधि थे। उनके अनुसार, हाजी अनवर अहमद खान के मामले (एआईआर, 1980 पुंज और हर 306) (सुप्रा) में डिवीजन बेंच का फैसला इस मामले में सही कानून और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को बताता है। नागलिंगम, एआईआर 1972 अंध प्रा 340 (जिसे वीरमाचनेनी वेंकट नारायणा के मामले में डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था (आईएलआर (1975) अंध पिया 242) (सुप्रा) सही दृष्टिकोण था। विद्वान वकील के अनुसार, पदाधिकारियों ने माना प्रबंध समिति के सदस्यों की मर्जी के दौरान कार्यालय। हालाँकि, विद्वान वकील ने चुपचाप स्वीकार किया कि यदि पदाधिकारियों का कार्यकाल क़ानून या उपनियमों की शर्तों के तहत तय किया गया है, तो एक विशिष्ट शक्ति होनी चाहिए अविश्वास मत द्वारा उन्हें हटाने के लिए। विद्वान वकील के अनुसार, हरियाणा अधिनियम, नियमों या उपनियमों में पदाधिकारियों का कोई कार्यकाल तय नहीं किया गया है।

14. संबंधित पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि श्री खोजी के तर्क मान्य होने चाहिए। वीरमाचानेनी वेंकट नारायण के मामले (आईएलआर (1975) अंध प्रा 242) (सुप्रा) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किया गया विचार सही दृष्टिकोण है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष मामला भी सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत था , जहां पदाधिकारियों का कार्यकाल भी उपनियमों द्वारा तय किया गया था, लेकिन अधिनियम, नियमों या के तहत कोई शक्ति नहीं थी। प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदाधिकारियों को हटाने हेतु उपविधि। जहाँ तक समिति के सदस्यों का सवाल है, उन्हें केवल सामान्य सभा द्वारा ही हटाया जा सकता था। डिवीजन बेंच के न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अविश्वास मत द्वारा हटाने की शक्ति को किसी क़ानून में पढ़ा या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है या इसे एक निहित शक्ति के रूप में लिया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा में हमारे अपने अधिनियमों की बात करें तो, पंजाब अधिनियम में धारा 27 , नियम 25 और 26 जो पहले ही ऊपर उद्धृत किए जा चुके हैं, उनमें निष्कासन और उन परिस्थितियों का प्रावधान है जिनमें किसी समिति के सदस्य को हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह शक्ति प्रदान करती है कि किसी पदाधिकारी को अविश्वास मत द्वारा हटाया जा सकता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि किसी पदाधिकारी को भी केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसा कि नियमों के नियम 25 और 26 के साथ पठित धारा 27 में दिया गया है।

15. पंजाब पंचायत समितियाँ और जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 18 में पदाधिकारियों के कार्यकाल का निर्धारण किया गया है और साथ ही अविश्वास मत द्वारा पदाधिकारियों को हटाने की शक्ति भी दी गई है। इसी प्रकार, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (धारा 9) में, पंचों/सरपंचों के कार्यालय का कार्यकाल निर्दिष्ट किया गया है और साथ ही वोट द्वारा हटाने की शक्ति भी निर्दिष्ट की गई है।

विश्वास प्रदान किया गया है. यहां तक कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (धारा 21 और 22) में भी कार्यकाल तय किया गया है और अविश्वास मत द्वारा हटाने की शक्ति निर्दिष्ट की गई है। यदि उसी विधायिका ने कुछ अन्य स्थानीय निकायों के लिए विशेष रूप से अविश्वास मत द्वारा पदाधिकारियों को हटाने की शक्ति प्रदान की है, तो पंजाब और हरियाणा के सहकारी अधिनियमों में ऐसी शक्ति का लोप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क़ानूनों में चूक को हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसे मैक्सवेल के इंटरपोलेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, बारहवें संस्करण के पृष्ठ 33 पर बताया गया है:

"यह शाब्दिक निर्माण के सामान्य नियम का एक परिणाम है कि किसी क़ानून में कुछ भी जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता है जब तक कि इस अनुमान को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार न हों कि विधायिका का इरादा कुछ ऐसा था जिसे उसने व्यक्त करना छोड़ दिया, लॉर्ड मर्सी ने कहा 'यह है संसद के अधिनियम में उन शब्दों को पढ़ना एक मजबूत बात है जो वहां नहीं हैं, और स्पष्ट आवश्यकता के अभाव में ऐसा करना एक गलत बात है।' (थॉम्पसन बनाम गूल्ड एंड कंपनी । (1910 एसी 409)। 'हम नहीं हैं लॉर्ड लोर बर्न एलसी ने कहा, 'संसद के अधिनियम में शब्दों को पढ़ें, जब तक कि इसके लिए स्पष्ट कारण अधिनियम के चारों कोनों में न पाया जाए। (विकर्स, संस, और मैक्सिम, लिमिटेड बनाम इवांस (1910) एसी 444)"।

सहकारी अधिनियमों और नियमों में इस चूक के मद्देनजर , हमारी राय है कि विधायिका ने कभी भी समिति के सदस्यों/बैंक के निदेशकों को अविश्वास मत द्वारा हटाने की ऐसी शक्ति देने का इरादा नहीं किया था।

16. हिंदूराव बलवंत पाटिल मामले (एआईआर 1982 बॉम्बे 216) (सुप्रा), जो कि सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत भी एक मामला था , में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उपरोक्त प्रस्ताव से निपटते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया: - -

"चुनाव लड़ने का अधिकार और चुनाव रद्द करने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार या पहले से ही निर्वाचित व्यक्ति को वापस बुलाने का अधिकार सामान्य कानून अधिकार नहीं हैं। इन अधिकारों को क़ानून द्वारा प्रदत्त किया जाना चाहिए और इसलिए इन्हें केवल विषय के अनुसार ही लागू किया जा सकता है संबंधित क़ानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार। अनुच्छेद 19(1)(सी) द्वारा गारंटीकृत अधिकार सभी नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार है। यह एक ऐसा अधिकार है जिसका आनंद हर कोई उठा सकता है। इसका कोई संदर्भ नहीं है किसी विशेष क़ानून द्वारा प्रदत्त या निर्मित अधिकार।

सहकारी समिति अधिनियम भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है। सहकारी आन्दोलन एक सामाजिक-आर्थिक एवं नैतिक आन्दोलन है। कम से कम यह कहा जाए तो यह सत्ता के विकेन्द्रीकरण और विकेंद्रीकरण की योजना का एक हिस्सा है। सामूहिक शक्ति के नशे की तुलना सहयोग से नहीं की जा सकती। उक्त आंदोलन की प्रकृति में यह न केवल स्व-विनियमित होना चाहिए, बल्कि आंदोलन में बाधाएं और प्रतिबंध भी अंतर्निहित हैं। क़ानून द्वारा प्रदत्त या निर्मित अधिकार कर्तव्य के साथ जुड़े हुए हैं। कार्यकाल की निश्चितता समाज के उचित प्रशासन और प्रबंधन में मदद करती है। सहकारी आंदोलन को आंतरिक या व्यक्तिगत हड़ताल से प्रदूषित या अवरुद्ध होने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही इसे दलगत राजनीति से

प्रदूषित होने की अनुमति दी जा सकती है। जब भी विधायिका को लगता है कि कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसे हटाने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाते हैं। एक व्यक्ति को एक विशेष कार्यकाल के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उनका कार्यालय अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। यह वसीयत में एक कार्यालय नहीं है और इसलिए, ऐसे कार्यालय पर सामान्य खंड अधिनियम की धारा 16 लागू नहीं हो सकती है।"

बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीरमाचानेनी वेंकट नारायण के मामले (आईएलआर (1975) अंध प्रा 242) (सुप्रा) में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया। हम उपर्युक्त मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव से सम्मानजनक सहमत हैं।

17. जोगिंदर सिंह (1977 पुन एलजे 310) (सुप्रा) में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का फैसला वास्तव में हमारे सामने मौजूद मुद्दे को नहीं छूता है और यह किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं करता है। वहां पार्टियों को सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर करने के लिए बाध्य किया गया ।

18. अब हाजी अनवर अहमद खान के मामले (एआईआर 1980 पुंज और हर 306) (सुप्रा) में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर आते हैं, मामले का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीशों ने जनरल क्लॉज एक्ट के प्रावधानों के साथ-साथ प्रावधानों पर भी भरोसा किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 372(1) में यह माना गया है कि निकाय के पास एक अंतर्निहित शक्ति है जो किसी पदाधिकारी को अविश्वास मत द्वारा हटाने के लिए चुनती है। उन्होंने भारत के संविधान के सामान्य खंड अधिनियम और अनुच्छेद 372(1) के प्रावधानों का सहारा लेते हुए वीरमाचानेनी वेंकट नारायण के मामले (आईएलआर (1975) अंध प्रा 242) (सुप्रा) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच को अलग कर दिया। शुरुआत में यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह वक्फ अधिनियम , 1954 के तहत मामला था। हालांकि फैसले में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है , लेकिन हमारे अनुसार, संदर्भ कथित तौर पर था पंजाब जनरल क्लॉज एक्ट, 1898 की धारा 14, जो इस प्रकार है : --

"14. नियुक्ति करने की शक्ति में निलंबित करने या बर्खास्त करने की शक्ति शामिल है। जहां किसी भी पंजाब अधिनियम द्वारा कोई नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की जाती है, वहां, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो, नियुक्ति करने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी भी उस शक्ति का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा या उसके द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को निलंबित या बर्खास्त करने की शक्ति है।"

हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार , समान प्रावधान सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 16 में निहित है। पंजाब सेंट्रल क्लॉजेज एक्ट, 1898 की धारा 14 (जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1897 की धारा 16 के बराबर), केवल उस प्राधिकारी में हटाने की अंतर्निहित शक्ति की बात करती है जिसके पास नियुक्ति की शक्ति थी। यह धारा किसी पदाधिकारी या किसी पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 14 सार्वजनिक सेवा में की गई नियुक्तियों के मामलों में लागू की जानी है, न कि किसी निर्वाचित कार्यालय में।

19. संविधान का अनुच्छेद 372(1) निम्नलिखित शब्दों में है:--

"372(1)। अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधिनियमों के इस संविधान द्वारा निरसन के बावजूद, लेकिन इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन, इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून जारी रहेंगे। सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित किए जाने तक इसे लागू रखें।"

20. अनुच्छेद 372 जैसा कि ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, केवल यह प्रदान करता है कि संविधान द्वारा अधिनियमितियों के निरसन के बावजूद, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 395 के तहत संदर्भित किया गया है, संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू कानून जारी रहेंगे। सक्षम विधायिका/प्राधिकरण द्वारा परिवर्तन या दोहराए जाने तक लागू। हाजी अनवर अहमद खान के मामले (एआईआर 1980 पुंज और हर 306) (सुप्रा) में डिवीजन बेंच ने देखा कि वीरमाचानेनी वेंकट नारायण के मामले (आईएलआर (1975) अंध प्रा 242) (सुप्रा) में आंध्र प्रदेश की डिवीजन बेंच ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उपर्युक्त अनुच्छेद के प्रावधानों और भारत में लागू सामान्य कानून के सिद्धांतों के आवेदन के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया। जैसा कि हिंदूराव बलवंत पाटिल के मामले (एआईआर 1982 बॉम्बे 216) (सुप्रा) में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर चर्चा करते समय पहले ही देखा गया था, चुनाव लड़ने का अधिकार और चुनाव को रद्द करने का अधिकार या चुनाव वापस लेने का अधिकार पहले से ही निर्वाचित व्यक्ति सामान्य कानून अधिकार नहीं हैं। अन्यथा भी, हमारा विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 372(1) का कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि संविधान के लागू होने से पहले कोई मौजूदा कानून नहीं था, जो सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार देता हो। प्रस्ताव, जिसे संविधान के अनुच्छेद 372(1) के तहत बचाया जाना था ।

21. हमने स्थानीय निकायों के अन्य अधिनियमों जैसे जिला, परिषद अधिनियम, पंजाब नगरपालिका अधिनियम और पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम का अध्ययन किया है, जहां पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान हैं। लेकिन हमने पाया है कि ऐसे उद्देश्यों के लिए बैठक बुलाने और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा किसी पदाधिकारी को हटाने के लिए आवश्यक बहुमत के संबंध में ऐसे प्रावधानों को बहुत कठोर बना दिया गया है। इन अधिनियमों के तहत सामान्य प्रस्ताव केवल बहुमत से पारित किये जाते हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के मामले में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि हम सहकारी अधिनियम , नियमों या उपनियमों में ऐसी शक्ति पढ़ते हैं कि बहुमत से किसी पदाधिकारी को हटाया जा सकता है तो इससे प्रबंध समिति/बोर्ड के रूप में बहुत ही अराजक स्थिति पैदा हो सकती है। जो निदेशक हमेशा बहुत कम संख्या में होते हैं, वहां हर दूसरे दिन किसी न किसी पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की नौबत आ ही जाती है. यदि अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐसा अधिकार अनुमान लगाया जाए या यह माना जाए कि यह उस निकाय में निहित है जो पदाधिकारियों का चुनाव करता है, तो इसका मतलब यह होगा कि सामान्य निकाय भी अविश्वास का वोट दे सकता है किसी सदस्य को प्रबंध समिति की सदस्यता से हटाना। यह वास्तव में सहकारी आंदोलन की पूरी अवधारणा को उलट देगा।

22. उपरोक्त कारणों से. फैसले की शुरुआत में उठाए गए सवाल का जवाब यह है कि पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1961, नियमों और उसके तहत बनाए गए उपनियमों (साथ ही हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984) में कोई प्रावधान नहीं है। किसी सहकारी बैंक की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/निदेशक मंडल के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नियम और उसके तहत बनाए गए उपनियम) ऐसे प्रस्ताव को पेश करने की

अनुमति नहीं है। किसी शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और न ही ऐसी शक्ति बैंक की प्रबंध समिति/निदेशक के सदस्यों में निहित है। पदाधिकारियों को केवल अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित नियमों के नियम 25 और 26 के अनुसार ही हटाया जा सकता है। सम्मान के साथ हम हाजी अनवर खान के मामले (एआईआर 1980 पुंज और हर 306) (सुप्रा) (जो वक्फ अधिनियम के तहत एक मामला था) में डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून से सहमत होने में असमर्थ हैं, हमारी राय में, यह लागू नहीं होता है नीचे सही कानून.

23. परिणामस्वरूप, दोनों रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं और संबंधित बैंकों के अध्यक्ष/अध्यक्ष को हटाने के लिए पारित प्रस्तावों को रद्द कर दिया जाता है। पार्टियों को अपनी लागत सुनने के लिए छोड़ दिया गया है।

24. याचिकाएँ स्वीकार की गईं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)